up the matter with the UAE Government, and the UAE Government was very much cooperative, and they have finally informed that he was not there in the UAE.

. DR. K. MALAISAMY: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether he has any idea about the total number of Indian criminals abroad. That is number one. (*Interruptions*) I would like to know whether you have any rough idea in this regard. ...(*Interruptions*) They should allow me to complete my question.

Secondly, I would like to know whether you have got an analysis of the type of crimes that these people are committing outside the country. Has there been any categorisation in terms of terrorism, this offence or that offence?

SHRI RAJEEV SHUKLA: If an Indian is wanted by another country, or, if his extradition is sought, I would like to know from the hon. Minister whether that Indian can approach the Indian authority for release or not. Secondly, to what extent America is cooperating as far as extradition is concerned?

SHRI E. AHAMMED: Mr. Chairman, Sir, if an Indian's extradition is sought by another country, as I mentioned here, firstly we will appoint a magistrate to try the case here. If the magistrate also orders that he should be extradited, the person has the right, under section 29 of the Extradition Act, to approach the Central Government, and the Central Government decides...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please don't repeat. You have already spoken on this matter.

SHRI E. AHAMMED: The Government of India considers three things: whether the case is of a criminal nature, whether any *mala fide* case is there, and whether there is a political consideration. On the basis of these three considerations, the Government of India will take a final decision.

Jobs to unemployed youths

*325. SHRI BHAGWATI SINGH: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the number of educated unemployed persons in the country, State-wise;

(b) whether it is a fact that Government are forming a scheme for providing jobs to unemployed educated youth in the country; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI K. CHANDRASEKHAR RAO): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) State-wise, details of the number of educated (10th Standard & above) job seekers, all of whom are not necessarily unemployed, on the live register of employment exchanges in the country as on December 2002 (latest available) are given in the enclosed Statement-I (See below)

(b) and (c) Government is targeting creation of 5 crore employment opportunities during the Tenth Plan period.

Statement-I

No. of Educated (10th & Above) Job Seekers on The Live Register of Employment Exchanges As On 31.12.2002

(In thousands)

Sl.No.	State	Live Register
1.	Andhra Pradesh	2872.2
2.	Arunachal Pradesh	12.2
3.	Assam	1024.9
4.	Bihar	1484.1
5.	Chhattisgarh	800.3
6.	Delhi	845.1
7.	Goa	84.1
8.	Gujarat	864.4
9.	Haryana	596.8
10.	Himachal Pradesh	695.6
11.	Jammu & Kashmir	90.7
12.	Jharkhand	709.7

Sl.No.	State	Live Register
13.	Karnataka	1273.1
14.	Kerala	3026.4
15.	Madhya Pradesh	1474.0
16.	Maharashtra	3350.2
17.	Manipur	263.2
18.	Meghalaya	20.3
19.	Mizoram	21.6
20.	Nagaland	21.5
21.	Orissa	618.2
22.	Punjab	383.1
23.	Rajasthan	523.1
24.	Sikkim*	—
25.	Tamilnadu	3128.7
26.	Tripura	105.7
27.	Uttranchal	275.7
28.	Uttar Pradesh	1392.0
29.	West Bengal	3483.9
30.	Andaman & Nicobar	16.9
31.	Chandigarh	57.3
32.	Dadra & Nagar Haveli	4.0
33.	Daman & Diu	4.5
34.	Lakshdweep	5.7
35.	Pondicherry	138.8
	GRAND TOTAL :	29667.9

*No Employment Exchange is functioning in this State.
Figures may not tally due to rounding off.

श्री भगवती सिंह: सभापति महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए क्योंकि माननीय मंत्री जी से मैंने जो प्रश्न किया है, उसका जवाब उन्होंने टाला है। मेरा सीधा प्रश्न यह है कि देश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की राज्यवार संख्या क्या है? माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें कहा है कि दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले शिक्षितों, यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। मान्यवर यह सही है कि जितने बेरोजगार हैं, उनके नाम रोजगार

कार्यालय में दर्ज नहीं होते, लेकिन मेरा जो प्रश्न था, वह यह था कि देश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की राज्यवार संख्या क्या है? यह संख्या सरकार के पास होनी चाहिए कि देश में कितने बेरोजगार हैं और अगर यह संख्या नहीं है, तो बेरोजगारी को खत्म करने की योजना सरकार कैसे बनाएगी यह विचारणीय प्रश्न है।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है। इतने का ही जवाब मिल जाए तो बहुत है।

श्री भगवती सिंह: मान्यवर, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है.....

श्री सभापति: आप क्यों उनके ऊपर बर्डन डाल रहे हो? पहले इसका तो जवाब देने दीजिए।

श्री भगवती सिंह: मान्यवर, जो मेरा प्रश्न है, पहले मैं पूछ लूं, उसी में वे जवाब दे देंगे। प्रश्न यह है कि शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को जब तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक बेरोजगारी भत्ता देने संबंधी सरकार की योजना क्या है? यह नंबर एक है। माननीय मंत्री जी, आप यह भी बताने की कृपा करें कि शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की समस्या पर अध्ययन कराने के लिए किसी आयोग या समिति का गठन किया है या करने जा रहे हैं? यदि किया है तो उनकी समस्याएं क्या है? मान्यवर, मेरा एक प्रश्न और है?

श्री सभापति: मैं आपको और एलाउ नहीं करूंगा। आप बैठ जाइए। आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब मैं दे देता हूं कि इस पर योजना आयोग विचार कर रहा है।

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Sir, the question pertains to educated unemployed youth. A list of such persons, State-wise, has been placed before the House. I am sure this has also eben received by the Hon. Member.

Sir, the employment generation has been seen as a part of the normal growth process. The Tenth Plan envisages to target about 5-crore employment opportunities in the country. The Mid-Term Appraisal also says that the programme is in consonance with the target. Unemployed educated youth, उनके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम या कोई स्पेशल आयोग गठित करने की बात नहीं है।

This incorporate the process of the normal growth process.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, सबसे पहले तो मैं प्रश्नकर्त्ता के साथ स्वयं को सम्बद्ध करते हुए, यह कहना चाहूंगी कि मैं शतप्रतिशत सहमत हूं कि मंत्री जी ने उनके प्रश्न का

जवाब देने की बजाए, टाला है। उन्होंने जो जवाब दिया है, वह भी आधा-अधूरा जवाब है। चूंकि यह प्रश्न शिक्षित बेरोजगारों के बारे में है और भाग 'ख' में मंत्री जी ने कहा है कि सरकार ने दसवीं योजना अवधि के दौरान पांच करोड़ रोजगार अवसरों के सृजन का लक्ष्य रखा है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि इन पांच करोड़ रोजगार के अवसरों में शिक्षित बेरोजगारों को कितने रोजगार देने की बात है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने क्या योजना बनाई है? क्योंकि सवाल योजना के बारे में था, लेकिन जब आपने लक्ष्य रखा तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आपने क्या कोई योजना भी बनाई है और इन पांच करोड़ शिक्षित बेरोजगारों को कितना रोजगार दिया जाएगा?

श्री के॰ चन्द्रशेखर राव: सर, एजुकेटिड अनएम्लॉइड यूथ के लिए कोई खास योजना नहीं है और इसमें किसी बात को छिपाने की जरूरत भी नही है। As I mentioned earlier, the employment generation is always seen and observed as a part of the normal growth process. It is not separate. The UPA Government is committed and made it very clear in the CMP that, along with vastly expanding credit facility for small-scale industry and self-employment, it will ensure that the services industry will be given all support to fulfil its true growth and employment potential which includes software, all IT-enabled services, trade, distribution, transportation, telecommunications, finance and tourism. Apart from the...

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है,

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, शिक्षित बेरोजगारों के लिए कोई योजना नहीं है?

श्री सभापति: एक मिनट, आप बैठिए। श्री नीलोत्पल बसु।

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Sir, this is what I am trying to say. Apart from the labour-intensive programmes taken up by the Government, these sectors will definitely यह जो शिक्षित बेरोजगारों की बात हो रही है, ये जो सेक्टर्स हैं जिनपर गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रेस दिया जा रहा है, इसमें उनके लिए ज्यादा अपोर्चुनिटी मिलेंगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, मंत्री जी को भी स्वयं अभी रोजगार मिला है इसलिए इन्हें मालूम है कि बेरोजगारों की पीड़ा क्या होती है? अगर कोई योजना नहीं है तो शिक्षित बेरोजगारा क्या करेंगे?

श्री सभापति: बोलने दीजिए, प्लीज टेक योर सीट।

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, my regret, after having read the reply, is that there seems to be no change in the attitude of the Government

after the elections because the 5-crore figure that has been quoted in the reply was a major bone of contention between the earlier Government and all of us. It is because that figure and the way it was sought to be reached by the earlier Government were challenged by all of us. The issue is very clear. You have quoted one portion of the CMP. Could you tell us, since the Bill for the Employment Guarantee has now been circulated, why the Government felt it unnecessary to include the urban aeras for bringing them within the purview of that Act, which would have addressed the question of educated unemployment, particularly in the urban areas?

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Sir, for the unorganised sector employment intensified activities एक एक्ट बन रहा है। That will speak about unorganised labour force. इसमें कोई शक नहीं है, मैं कोई बात छिपाना नहीं चाहूंगा कि एजूकेटिड अनएम्प्लोएड लोगों के लिए अभी तक कोई खास योजना नहीं है।

श्री नीलोत्पल बसु: मंत्री जी, आप मेरा सवाल समझ नहीं पाए इसलिए दोबारा सुन लीजिए, जो हमारा नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, यह जितना आपका है, उतना हमारा भी है, उसमें यह प्रावधान था कि तमाम बेरोजगारों के लिए हर परिवार में, किसी न किसी रूप में रोजगार की गारंटी देंगे। लेकिन जो बिल का प्रारूप देखने को मिला है, उसमें अरबन एरिया के लोगों को दर्ज नहीं किया गया है। इसका क्या कारण? यह जो सवाल उठता है, उसका आंशिक निदान हो सकता है, जो एजुकेडिट अनएम्पलोएड हैं, उनके लिए भी रोजगार की गारंटी हो सकती है।

DR. MANMOHAN SINGH: Sir, the hon. Member is right that the Common Minimum Programme does make a reference to both, the rural sector and the urban sector. The situation on the ground is that we have had a large number of programmes for the rural sector. We are going to develop these further and move towards a system of employment guarantee for unskilled labour. And, it is my hope that these programmes will grow in the years to come.

With regard to the urban sector, there are some programmes, like the Self-Employment Programme, Margin Money Schemes, etc. There are other programmes also with regard to other sectors. But I must confess to the House that our knowledge about the Characteristics of unemployment in urban areas is not that firm as is the case with rural areas. Therefore, for the time being, we felt let us make a beginning. The employment guarantee is being introduced in the rural areas. In the meanwhile, the Government has set up a commission under the

chairmanship of Dr. Arjun Sengupta to look into the problems of the activities in the unorganised sector. And these unorganised sector activities account for 93 per cent of our labour force. It is my hope that once the report of that commission becomes available, we will be able to elaborate programmes for the urban sector as well.

Single window facility for NRIs

*326. DR. T. SUBBARAMI REDDY.
PROF. ALKA BALRAM KSHATRIYA:††

Will the Minister of OVERSEAS INDIAN AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have planned a comprehensive single window facility for Non-Resident Indians and also special courts and a 23 point programme that will address pressing issues concerning the NRIs;

(b) if so, the details thereof;

(c) to what extent these proposals have been finalized and announced; and

(d) to what extent Government have been able to help the NRIs in a more systematic manner?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No, Sir/Madam.

(b) Question does not arise.

(c) The work allocation of the Ministry of Overseas Indian Affairs has been finalized and notified on 15th December, 2004. These cover 18 items.

(d) Now that the mandate of the Ministry of Overseas Indian Affairs has been finalized, it would work out its staff and budget requirements immediately. Thereafter, it would be possible for the Ministry to respond to the needs of NRIs and PIOs in a more systematic manner in all matters and in particular matters relating to citizenship, investment, philanthropy, education, insurance, Science and Technology, Emigration, etc.

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: सभापति जी, मॉरीशस में करीब 65 से 70 प्रतिशत भारतीय मूल के लोग रहते हैं और भारत से मॉरीशस के संबंध काफी पुराने हैं। मॉरीशस सरकार ने एक प्रावधान

††The question was actually asked on the floor of the house by Prof. Alka Balram Kshatriya.